उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आइ एम कालिंग दी मिनिस्टर ।

श्री राजनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात का पता लगाया जाये कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कितने टेलीफोन राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में हुए हैं । क्या इस तरह की तानाशाही चलेगी । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी, व्यक्तिगत तानाशाही नहीं चलेगी । एक व्यक्ति के पीछे आज सारे देश को तबाह किया जा रहा है । अगर देश के सारे साधनों का इस तरह से दुरुपयोग किया जायेगा तो यह देश डूब जायेगा । इसलिए मैंने कहा, ऐ निज-लिंगप्पा, तुम कितने बेहैया हो कि तुम आज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हो, तुम्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिये (*Interruptions*) उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये वरना उनका रहना निरर्थक है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मानसिंह वर्मा और श्री चित्त बासु ने जो मुद्दे इस विधेयक के सम्बन्ध में उठाये हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं । मानसिंह जी ने यह कहा कि हमें राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है और हमें अलगाव की भावना को दूर करना चाहिये । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य भी यही है । इस तरह की कुत्सित भावना जो फैलाना चाहते हैं उनको सजा देने का ही प्रावधान इस बिल में किया गया है । अलगाव की भावना फैला कर लोगों को अलग अलग करना, उनमें एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करना, एक दूसरे के मन में द्वेष पैदा कर के अलगाव की भावना पैदा करना, चाहे वह भाषा के प्रश्न पर हो, चाहे वह धर्म के प्रश्न पर हो, चाहे वह क्षेत्रीय भावना के प्रश्न पर हो, इन सब बातों को इसमें जुर्म करार दिया गया है । इसके साथ साथ इस बात का भी प्रावधान इसमें किया गया है कि जिन लोगों को इस तरह का कार्य करने के लिये सजा मिले उनका किसी तरह का कोई चुनाव का पद भी नहीं रहने दिया जाये । मैं समझता हूं कि जो भावनाएं माननीय सदस्यों के मन में हैं उन भावनाओं को मूर्तरूप देने का इसमें यत्न किया गया है । इसलिये मैं उम्मीद करता करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is:.

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We move on to the Delhi High Court (Amendment) Bill, 1969.

THE DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS. (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, under Section 5(2) of the Delhi High Court Act, 1966, the Delhi High Court has ordinary original civil jurisdiction in every suit the value of which exceeds twenty-hve thousand rupees. Under Section 17(3) of that Act the Delhi High Court has such original jurisdiction in respect of the Union territory of Himachal Pradesh also. After the establishment of the Delhi High Court it was found that the limit of twenty-five thousand rupees for civil suits was too low a figure for such a big metropolitan city like Delhi, and that the Hif?h Court had started accumulating arrears. It was therefore considered necessary, in the interests of speedy disposal of work in the High Court, that the present limit of twenty-five thousand rupees for original suits should be raised, and the High Court should have ordinary original civil jurisdiction only in suits whose value exceeds

[Shri K. S. Ramaswamy]

fifty thousand rupees. Consequently, the arbitration jurisdiction of the High Court will also, under the Arbitration Act, be correspondingly raised to suits whose value exceeds fifty thousand rupees. The Chief Justice of India and the Chief Justice of the Delhi High Court have strongly recommended this proposal.

In Article 112(3) of the Constitution relating to expenditure charged on the Consolidated Fund of India, there is no provision made to include the salaries and allowances of Judges of the High Court for a Union territory. So this opportunity has been taken to provide for the salaries and allowances of the Judges of this High Court to be charged on the Consolidated Fund of India.

Sir, this is the simple object of- the Bill and I hope the House will agree to take this Bill into consideration.

The question was proposed.

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : श्रीमन्, यह जो बिल आया है हाई कोर्ट दिल्ली के ऐक्ट में संशोधन करने के लिये तो जहां तक इसका क्लाज 2 है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजेज की सैलरीज और अलाउंसेज कंसालिडेटेड फंड आफ इंडिया पर चार्ज्ड अकाउंट होंगे मैं समझता हूं कि यह एक अनामली पुराने ऐक्ट में थी क्योंकि और दूसरे हाई कोर्ट के जजों का वेतन और भत्ता सब जगह चार्ज्ड अकाउंट ही होता है, वोटेड नहीं होता है, तो यह अनामली दूर करने की जो सरकार ने कोशिश की है, यह स्वागत करने की चीज है ।

बाकी दूसरे जो क्लाज हैं जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वेल्युएशन जो 25 हजार का था उसको बढ़ा कर के 50 हजार किया गया है, इसका उद्देश्य मैं समझता हूं कि यह दिल्ली हाई कोर्ट में एरियर्स पेंडिंग बहुत ज्यादा हैं, माउंटिंग एरियर्स पड़े हुए हैं, इसलिये उनका निष्पादन करने के लिये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कुछ और घटा कर के 50 हजार से नीचे के वैल्युएशन के मुकदमों को दूसरी छोटी अदालतों में सौंपने का प्रावधान इसमें किया गया है, जिससे जो मुकदमे लम्बिक हैं बहुत दिनों से उनका निष्पादन हो सके । मैं समझता हूं कि सरकार ने यह जो कदम उठाया है, यह सही है । लेकिन मुझे इस बात में आशंका है कि इस कदम के उठाने से ही सभी मुकदमों का निष्पादन हो सकेगा । क्योंकि हाई कोर्ट में सिविल केसेज बहुत कम होते हैं, हाई कोर्ट में सिविल केसेज की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि आजकल कांस्टिट्यूशनल केसेज की संख्या होती है । यह सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट का ही सवाल नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के और राज्यों के उच्च न्यायालयों में इसी तरह से मुकदमे बहुत दिनों के लंबित पड़े हुये हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी पड़े हुये हैं। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । जहां तक हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम कर के और छोटी छोटी अदालतों के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा कर के मुकदमों का निष्पादन करने का प्रयास है, वह सराहनीय है और उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन उसमें आंशिक सफलता ही मिलेगी, उसमें पूरी की पूरी सफलता नहीं मिल सकती है । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के तमाम राज्यों के हाई कोर्ट शनिवार को काम नहीं करते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक ही सब हाई कोर्ट काम करते हैं, इसलिये किसी शनिवार को अगर कोई गजेटेड छुट्टी हो या सैकेंड सैटरडे हो, तो उसको छोड़कर बाकी सभी शनिवार को अगर हाई कोर्टों में काम हो तो मुकदमों का निष्पादन बहुत ज्यादा हो सकता है ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि अभी हाई कोर्ट रोज पांच घंटे काम करते हैं जब कि सरकार के दूसरे दफ्तरों में करीब साढ़े छह घंटे रोज काम होता है, तो मुकदमों का

निष्पादन करने के लिये हाई कोर्ट के काम करने का समय भी कम से कम एक घंटा रोज़ बढ़ा दिया जाये। पांच घंटे के बजाये अगर वे छह घंटा रोज़ काम करें तो मैं समझता हूं कि एक घंटा रोज़ समय बढ़ाने पर काफी केसेज़ डिसपोज़ आफ हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ इस बिल में पुरानी अनामलीज़ को दूर करने के लिये और एरियर्स को खत्म करने के बारे में जो सरकार का प्रयास है उस प्रयास की मैं फिर सराहना करता हूं। लेकिन मुझे यह सन्देह है कि इससे आंशिक सफलता मिलेगी। इसकी ओर ध्यान दिला कर के मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और देता हूं कि हर शनिवार को भी हाई कोर्ट्स चलें और हाईकोर्ट्स का काम करने का समय पांच घंटे के बजाये छह घंटे कर दिया जाये क्योंकि इससे मुकदमों का निष्पादन ज्यादा हो सकता है।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : The main purpose of this measure, Mr. Vice-Chairman, Sir, is to reduce the number of civil suits that are triable by the Delhi High Court. Instead of the limit being twenty-five thousand rupees, as is the case at present, hereafter only suits of the value exceeding fifty thousand rupees can be filed. The reason is obvious; the work of the High Court is being reduced so that the number of pending suits in the High Court can be reduced Sir, the problem of mounting arrears in the various High Courts in the country and in the Supreme Court here is not a lone problem. The arrears are mounting not only in the top courts of the country but generally in various other courts of civil, criminal and subordinate jurisdiction also. Even at the Government level, whether it be the State Government or the Central Government, if one takes the number of pending files in each Ministry or in each Department of Government, we would set a very large number of pending files which await disposal by Government. But in the case of the courts the problem is slightly different because it has often been stated 'hat justice delayed is justice denied. It is therefore necessary, Sir, to ge into the question of mounting arrears in our High Courts and the eradication of such arrears not by the introduction of small measures like this confined to a particular High Court. I know that this is confined to the Delhi High Court but I would suggest that the problem has got to be tackled at a higher level. The problem cannot be solved by increasing the number of Judges. In many of the High Courts we have increased the number of Judges large enough but the cases are not being disposed of because even if you increase the number of Judges the work is largely confined in the hands of a few lawyers and they will not be available for conduct of cases and there are all sorts of practical difficulties. I would therefore suggest that there should be no original jurisdiction to try civil cases with any High Court. This Delhi High Court (Amendment) Bill ought to have incorporated a provision to remove the original jurisdiction of the High Court in so far as trial of civil cases are concerned. Quite a number of High Courts in the country, Sir, are not having such original jurisdiction. Some of the Presidency High Courts had such original jurisdiction but the Madras High Court has taken it away. A number of new High Courts are not having such jurisdiction. Calcutta and Bombay retain such jurisdiction and there are a number of Judges sitting on the original side of those High Courts. But we have found it by and large in the country as a whole a fair practice to entrust the trial of cases of unlimited jurisdiction to our Subordinate Judges and after the Subordinate Judges try these cases there is a cycle of appeals provided from their decisions to the High Court and to the Supreme Court. I would therefore suggest that this Bill ought not to have been merely for giving an upward.limit to the jurisdiction of the Delhi High ourt to begin with but should have completely abolished the original jurisdiction of the High Court.

Sir, with the way in which litigation is increasing in the country at the High Court level there cannot be any

[Shri K. Chandrasekharan] original jurisdiction at all except in regard to matters of a purely constitutional nature arising under articles 226, 227 and 228 of the Constitution. I would therefore submit to Government that the jurisdiction to try original cases on the civil side, on the criminal side and on the companies side that exists creates delays in the High Courts and it reduces the number of Judges available for dealing with civil and criminal appeals and constitutional cases. This original jurisdiction should be taken away from the High Courts ; then only it will be possible for Government to deal eifectively with the problem of mounting arrears in our high Courts.

In so far as this Bill does not seek to take away the original civil jurisdiction of the High Court certainly this measure has got to be opposed but in so far as it takes away a large part of the original jurisdiction the measure need not be opposed but certainly this measure cannot be supported except with an amount of anxiety that even with this measure the arrears in the Delhi High Court are not likely to be in any way substantially reduced.

Thank you.

SHRI K. S. RAMASWAMY : Sir, I am glad that hon. Members have welcomed this Bill though the hon. Mr. Chandrasekharan has objected to the original jurisdiction of the High Court. This original jurisdiction was conferred on this High Court under the Delhi High Court Act of 1966 and at that time this was discussed here threadbare before this jurisdiction was conferred on the Delhi High Court. The object of conferring original jurisdiction is that important cases of substantial value should be heard and disposed of by the High Court. A large number of suits come up especially in | a city like Delhi concerning various matters and it was thought that better justice will prevail if they were heard in the High Court. Hon. Members have made suggestions for reducing the arrears of the High Court. The Government is constituting a Committee of three Judges with the Chief Justice of India as Chairman to go into the causes of the arrears and to suggest some remedies. They will take into consideration all these suggestions.

Regarding the working time of the High Court, it is fixed by the various High Courts by the Chief Justices concerned and we cannot interfere in this matter but I hope the Committee will take all these suggestions into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. PI BHARGAVA) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 *were added to the Bill.*

Clause 1, the *Enacting Formula and the Title were added* to the *Bill.*

SHRI K. S. RAMASWAMY : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was nut and ine motion was adopted.

MOTION RE THE 16TH, 17TH AND18TH REPORTS OF THE UNIONPUBLIC SERVICE COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, I move :

"That the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the Union Public Service Commission for the periods from 1st April, 1985 to 31st March, 1966, 1st April, 1966 to 31st March, 1967 and 1st April, 1967 to 31st March, 1968, respectively together with the Government's Memoranda thereon laid on the Table of